

भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4412

20 अगस्त, 2025 को उत्तर देने के लिए

सकल घरेलू उत्पाद में अनुसंधान एवं विकास व्यय में वृद्धि

†4412. श्री ई. तुकाराम:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2029 तक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के कम से कम 1.5% तक बढ़ाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित रूपरेखा या कार्यनिति का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)**

(क) से (ग): सरकार ने 2029 तक अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 1.5% तक बढ़ाने का कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। देश में अनुसंधान एवं विकास (जीईआरडी) पर सकल व्यय पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और यह 2010-11 में 60,196.75 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 127,380.96 करोड़ रुपये अर्थात् दोगुना हो गया है। सरकार के दीर्घकालिक और विकासशील उद्देश्य हैं कि संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाया जाए। यह दृष्टिकोण देश में मज़बूत और टिकाऊ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इस उद्देश्य से, सरकार ने अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं। कुछ प्रमुख नीतिगत उपायों और संस्थागत अन्तःक्षेपों में शामिल हैं:

- वैज्ञानिक विभागों और अनुसंधान-उन्मुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एएनआरएफ अधिनियम, 2023 के माध्यम से अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) की स्थापना। केन्द्र

सरकार की ओर से 14,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है तथा अतिरिक्त धनराशि उद्योग, परोपकारी व्यक्तियों आदि जैसे गैर-सरकारी स्रोतों से प्राप्त की जाएगी।

- राष्ट्रीय मिशनों जैसे कि भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों के विकास में अग्रणी राष्ट्रों में से एक बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (बजट परिव्यय: 6,003.65 करोड़ रुपये); अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणाली राष्ट्रीय मिशन (बजट परिव्यय 3,660 करोड़ रुपये); राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन; एनआरएफ के एमएएचए (उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति के लिए मिशन) कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रिक वाहन-मिशन कार्यक्रम; भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (76,000 करोड़ रुपये); गहरे समुद्र के संसाधनों का पता लगाने और उनका स्थायी उपयोग करने के लिए डीप ओशन मिशन (बजट परिव्यय: 4077 करोड़ रुपये); स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन; और एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत एआई मिशन (बजट परिव्यय: 10,372 करोड़ रुपये) का शुभारंभ किया गया।
- सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर विषयक साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी केंद्रों का निर्माण करना
- निजी क्षेत्र, विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को सहायित और वित्तपोषित करने के लिए छह वर्षों में ₹1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना का शुभारंभ, जिससे विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- भू-स्थानिक नीति 2022, अंतरिक्ष नीति 2023, और बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति 2024 जैसे सक्षम नीतिगत ढाँचों को लागू करना।

इन पहलों का सामूहिक उद्देश्य भारत की अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को मजबूत करना, शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ाना तथा समय के साथ राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास व्यय में निरंतर वृद्धि के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना है।
